

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति में दिया गया वक्तव्य *

2010 की शरदऋतु में जब हम मिले थे उसके बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कई मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ा है जिसके फलस्वरूप बदलते परिदृश्य में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। आज हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हैं: क्या अभी भी उथल-पुथल भरी वित्तीय परिस्थितियों और पण्य मूल्यों में ऊर्ध्वमुखी दबावों के होते हुए भी बहाली सुनिश्चित है? भविष्य में आने वाली विकट परिस्थितियों को सहन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की आघात सहनीयता कितनी है? क्या वर्तमान में जारी सुधार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सशक्त बनाएंगे और इसे वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को ठहराव देने के संबंध में और भी अधिक प्रभावशाली बनाएंगे?

वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार

2. दुनिया भर में राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल सहित प्राकृतिक विपदाओं जैसे विभिन्न जोखिमों ने वैश्विक बहाली को और भी मुश्किल बना दिया है। वित्तीय परिस्थितियां संवेदनशील और अनिश्चित हो गई हैं साथ ही इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत प्रतिक्रिया आने का जोखिम भी है। आवर्ती सावरेन ऋण संबंधी आशंकाओं ने बाजार के विश्वास को प्रभावित किया है। संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार अभी भी बाकी है। अब जब कि संकट की चिंता खत्म हुई है तो उसकी जगह नई चुनौतियों ने ले ली है।

3. तेल की बढ़ती कीमतों के चलते वैश्विक बहाली खतरे में पड़ सकती है। विशेषतौर पर उभरते और विकासशील देशों के समक्ष आने वाले मुद्रास्फोटिकारी दबावों के अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के आने का खतरा बना हुआ है जब तक कि तेल की कीमतें वर्तमान दरों से कम नहीं हो जाती हैं। इसके अलावा 2010 के ग्रीष्मकाल से कई प्राकृतिक आपदाएं और परिणामी खाद्य आपूर्ति में कमी ठीक उसी समय हुई जब संकट के पश्चात मांग में पुनः वृद्धि आई। खराब मौसम और निम्न इनवेंटारियों के चलते भविष्य में होने वाली निम्न आपूर्ति संबंधी आशंकाओं के चलते विश्व खाद्य कीमतों में काफी वृद्धि

* श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के वित्त मंत्री और आइएमएफसी के सदस्य, जिसके अंतर्गत वे बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की ओर से डॉ. दुवुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 अप्रैल, 2011 को वाशिंगटन डीसी में दिया गया वक्तव्य।

आई है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। पण्य डेरिवेट बाजार की सद्गागत गतिविधियों के कारण मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

वैश्विक चुनौतियां और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका

4. अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के समक्ष पेश आ रही अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याएं नजदीक आ रहे संकट की पूर्व चेतावनी की पहचान करने और सूचना देने और वैश्विक चलनिधि के प्रबंधन संबंधी हमारी कमियों के चलते पैदा होती हैं। इस कारण अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में मूलभूत सुधार किए जाने हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अस्थिर पूंजीगत प्रवाहों को रोकने संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाए ताकि असंतुलनों और अस्थिरता के स्रोतों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय समायोजन तंत्र को मजबूत किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निगरानी

5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त कार्यों में निगरानी का कार्य काफी महत्वपूर्ण है। कमजोरियों पर ध्यान देने और संकट की शुरुआत का पता लगाकर यह वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिरता को बचाके रखने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों ही स्तरों पर प्रभावी कार्यान्वयन के द्वारा ही प्रभावी निगरानी प्रदान की जा सकती है। हम यह मानते हैं कि करार की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ही यह प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह आम सहमति बन जाती है कि कानूनी अधिदेश में कोई कमी है जिनके चलते प्रभावी कार्यान्वयन के मार्ग में बाधा आ रही है तो धाराओं में संशोधन करना अंतिम विकल्प होगा। निगरानी के विभिन्न स्तरों पर निरंतरता और व्यापकता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ईमानदारी और सभी के साथ समान व्यवहार - प्रणालीगत जोखिमों को बताया जाए, चाहे वे जहां से भी उत्पन्न हो रहे हों। हमें उन विकासशील देशों, जिन्होंने विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वास्तव में राजकोषीय विकास देखा है, के लिए स्क्रीनिंग के सख्त मानदंड अपनाकर इस बात पर बल देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बहुपक्षीय निगरानी के कारण विकसित देशों की सोवरेन ऋण संबंधी चिंताओं की अवहेलना न हो।

पूँजीगत प्रवाह का प्रबंधन

6. चूँकि उभरती और विकासशील देशों की स्थिति में सुधार ने गति पकड़ ली है, पूँजीगत प्रवाह भी संकट के पूर्व की स्थिति के समान हो गए हैं। इन प्रवाहों में काफी अस्थिरता दिखी है जिसके फलस्वरूप प्रवाहों के अचानक बंद होने और वापस लिए जाने की स्थिति में समष्टि आर्थिक अस्थिरता आई, परिणामतः प्रतिस्पर्धा में कमी आई और समष्टि आर्थिक नीतियां जटिल हो गईं। पूँजीगत प्रवाहों संबंधी नीति में निर्धारित बातों में एकरूपता होनी चाहिए। अब तक बड़े और अस्थिर प्रवाह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नीतिगत चयनों से होने वाले स्पिलओवर हैं, पूँजीगत प्रवाहों के प्रबंधन को केवल उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की समस्या के रूप में नहीं लेना चाहिए और समायोजन के बोझ को सभी के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। बोझ का वहन किए जाने के तरीके के परिणामस्वरूप बौद्धिक और व्यावहारिक दोनों ही चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।

7. जहां तक पूँजीगत प्रवाहों के प्रबंधन की बहुपक्षीय रणनीतियों का संबंध है, ऐसे रुख का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है जिसके अंतर्गत अस्थिर पूँजीगत अंतर्वाहों में बड़े उछाल झेल रहे सदस्य देशों के नीतिगत प्रतिसादों को स्थापित, मानकीकृत, प्राथमिकता के आधार पर रखने अथवा उनकी सीमा को निश्चित करने की कोशिश की गई हो। उनके अनुभवों के आधार पर, नीतिनिर्माताओं में लचीलापन और विवेक होना चाहिए ताकि वे किसी विशेष लिखत के बारे में लांछन लगने की भावना से मुक्त होकर उन नीतियों को अपना सकें जिन्हें वे समष्टिआर्थिक, मितव्ययी और पूँजीखातागत प्रबंध नीतियों के माध्यम से जोखिमों को कम करने के संबंध में उचित मानते हैं। इन मुद्दों के संबंध में सदस्य देशों की जानकारी की स्थिति को देखते हुए ऐसे देशों की पूँजीखातागत नीतियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिकार दिए जाने अथवा इस संबंध में इन पर बाध्यता अधिरोपित करने के लिए धाराओं को संशोधित करने पर विचार करना बहुत ही अपरिपक्व होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधन

8. हम 2008 के कोटा सुधारों की अभिपुष्टि का स्वागत करते हैं। इस प्रक्रिया में अगला कदम होगा 2010 के कोटा और अभिशासन सुधारों की त्वरित अभिपुष्टि और कार्यान्वयन। कोटा फॉर्मूला की एक व्यापक समीक्षा जनवरी 2013 तक समाप्त कर ली जाएगी ताकि जनवरी 2014 तक कोटा की पंद्रहवीं साधारण समीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो सके जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सक्रिय उभरते और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में अब तक की मामूली वृद्धि

को आगे बढ़ाएगा जो कि परिवर्तित होते वैश्विक आर्थिक सच्चाइयों को परिलक्षित करेगा। हमें 2012 की वार्षिक बैठक से पूर्व 2010 के सुधारों को पूरा करने के भरसक प्रयास करने चाहिए।

9. हम उधार लेने की विस्तारित और संशोधित नई व्यवस्था (एनएबी) का स्वागत करते हैं जो 11 मार्च 2011 से प्रभावी हुई। एनएबी सक्रिय करने को वर्तमान प्रत्याशाओं और 14 वीं साधारण समीक्षा के अंतर्गत उच्च कोटा संसाधनों की उपलब्धता के बीच सेतु के रूप में माना जाएगा। परिणामतः एनएबी को कम महत्व दिया जाना चाहिए ताकि एक संस्था के रूप में अइएमएफ, जो कि अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है, की कोटा आधारित छवि को बचा कर रखा जा सके।

आरक्षित निधि पर्याप्तता

10. हमारे विचार से पूँजी के खत्म हो जाने के कारण विकास में अचानक आने वाली रुकावट के संबंध में जो सुरक्षा आरक्षित निधियां उपलब्ध कराती हैं वह अवसर लागत से कहीं अधिक हैं। देशों द्वारा आरक्षित निधियों को एकत्र करना वैश्विक सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से जब आरक्षित निधियों का एकत्रीकरण चालू खाते के घाटे के संबंध में होता है।

11. आरक्षित निधि पर्याप्तता के किसी भी आकलन में देश-विशिष्ट की निहित परिस्थितियां, परिशुद्ध विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक आधार और व्यावहारिक अनुभव आधारित निर्णय परिलक्षित होने चाहिए। समष्टि आर्थिक और विवेकपूर्ण ढांचे और नीतियों पर विचार किया जाना चाहिए और साथ ही आकस्मिक वित्तीयन के वैकल्पिक प्रकार, देश की सुरक्षा और आरक्षित निधि पर्याप्तता के संबंध में समग्र आस्तियों और देयताओं, जिन्हें एक फार्मूले के अंतर्गत आसानी से नहीं रखा जा सकता है, पर भी विचार किया जाना चाहिए। पूँजीगत प्रवाह की अस्थिरता झेल रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में नए वित्तीयन का अचानक रुक जाना, विदेशी संविभाग निवेश, पूँजी पलायन और चालू खाता संवेदनशीलताओं सहित आरक्षित निधियों के संभावित पलायन से संबंधित व्यापक परिदृश्य से परे विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आरक्षित निधि पर्याप्तता से संबंधित प्रश्न को सुरक्षित आरक्षित निधि आस्तियों में कमी के व्यापक मुद्दे पर विचार किए बिना हल नहीं किया जा सकता है।

मुद्रा अंतरराष्ट्रीयकरण और विशेष आहरण अधिकार की भूमिका

12. सिद्धांत रूप में बहु-मुद्रा प्रणाली का विकास करना वांछनीय है जिसमें व्यापक विकल्पों के रूप में कई मुद्राएं परिचालनरत हों और जो बदलते आर्थिक भारों और वैश्विक यथार्थों को परिलक्षित

करे। इस संबंध में हमने यह देखा कि हाल में विकसित होती अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए संभावित आरक्षित निधि के रूप में विशेष आहरण अधिकार के प्रयोग को बढ़ा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रयास किए गए। विशेष आहरण अधिकार द्वारा इस महत्वपूर्ण भूमिका के निभाए जाने के संबंध में कई पूर्वापेक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है। विशेष आहरण अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की देयता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसे विभिन्न देशों में लेनदेन के संबंध में भुगतान के माध्यम के रूप में स्वतः स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, यह आसानी से खरीदने और बेचने योग्य होना चाहिए और इसके मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। चूंकि विशेष आहरण अधिकार इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, यह अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में आरक्षित मुद्रा के रूप में नहीं रह सकता है। सिद्धान्त रूप में, विशेष आहरण अधिकार को जारी करने के लिए वैश्विक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होगी जो वैश्विक भुगतान और निपटान प्रणाली की यूनिट की विशेषता है। इस तरह से हम बहु-मुद्रा वाले विश्व की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे का एक आयाम यह भी है कि विशेष आहरण अधिकार बास्केट के संघटन को बदल दिया जाए। हम हाल में की गई पहलों पर ध्यान दें तो यदि विशेष आहरण अधिकार बास्केट के संघटन को बदलने के प्रयास किए गए हैं तो हम उन सक्रिय रूप से उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को इसमें शामिल करने पर विचार कर सकते हैं जो वर्तमान समावेशन मानदंडों को पूरा करते हैं: विशिष्टरूप से एक पूर्णतः परिवर्तनशील पूंजी खाता और बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर।

निर्वाचन क्षेत्र में विकास

13. मैं अब अपने क्षेत्र के देशों की गतिविधियों के संबंध में बात करूंगा।

बांग्लादेश

14. बांग्लादेश तेजी से उच्च प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है जो कि व्यापक रूप से समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और कृषि क्षेत्र में सतत रूप से उच्च निष्पादन द्वारा समर्थित है। 30 प्रतिशत पर निर्धारित निर्यात वृद्धि और आंतरिक विप्रेषणों से बाह्य क्षेत्र व्यावहारिकता को काफी लाभ पहुंचा है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सम्मिलित प्रयासों ने निवेश वातावरण में सुधार किया है। तथापि, ईंधन, खाद्य, और उर्वरकों के वैश्विक मूल्यों के दबावों से होड़ लगाती बढ़ी हुई आंतरिक

कीमतों के साथ मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। फरवरी 2011 तक राजस्व संग्रहण में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप राजकोषीय स्थिरता मजबूत हुई है। बजट घाटे को सकल देशी उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है जिसके फलस्वरूप समग्र समष्टि आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी। चूंकि देशी मांग की तुलना में आयात की मांग बढ़ी है इसलिए भुगतान संतुलन में कुछ भार पड़ सकता है, यद्यपि विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर चार महीनों के आयात के स्तर की तुलना में पर्याप्त बना रहेगा। तदनुसार, मौद्रिक नीति को सख्त किया जा रहा है जिसमें विनिमय दर को घटने दिया जा रहा है ताकि वह भुगतान संतुलन को सहारा दे सके। मध्यावधि में देशी और विदेशी निवेशों में विशेषतौर पर बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी और सरकारी भागीदारी के संदर्भ में आने वाली बाधाओं को धीरे-धीरे हटाने से बांग्लादेश स्थायी द्विअंकीय वृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

भूटान

15. भूटान के विकास की गति मजबूत और विवेकपूर्ण तथा कुशल समष्टिआर्थिक प्रबंधन द्वारा समर्थित रही है। वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि 2009-10 में बढ़कर लगभग 9 प्रतिशत हो गई जो पनबिजली, निर्माण और सेवा क्षेत्र में आई तेज वृद्धि के फलस्वरूप संभव हुआ। तथापि, 2010 की समाप्ति के समय मुद्रास्फीति बढ़कर 9 प्रतिशत पर पहुंच गई। पनबिजली क्षेत्र में आयात में हुई तीव्र वृद्धि के कारण चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल देशी उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत हो गया है, किन्तु बड़ी मात्रा में अनुदानों और ऋणों के वितरण के चलते समग्र भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति में बना रहा। आरक्षित निधि की स्थिति में सुधार हुआ है और इसकी स्थिति बेहतर बनी हुई है। ऋण में तेज वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण था आवासन और निर्माण क्षेत्र और साथ ही व्यक्तिगत ऋण। भूटान का वित्तीय क्षेत्र वैश्विक वित्तीय संकट से अच्छी तरह से उबर गया और वित्तीय स्थिरता संकेतक बेहतर स्थिति में हैं।

भारत

16. भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर कृषिगत आउटपुट, मजबूत निजी उपभोग, जबर्दस्त निवेश और निर्यातों में आयी तेजी के चलते 2010-11 में 8.6 प्रतिशत की सकल देशी उत्पाद वृद्धि के साथ मजबूत हुई है। तथापि, मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है। हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य मुद्रास्फीति में आई मंदी के बावजूद मजबूत बनी रही क्योंकि बढ़ती हुई इनपुट लागतों के कारण विनिर्मित उत्पादों की

मुद्रास्फीति में भी हुई वृद्धि के साथ सामान्यीकृत मूल्य दबाव उभर कर सामने आए हैं। वैश्विक पण्य मूल्यों की बढ़ती कीमतों, विशेषतौर पर तेल के मूल्यों के चलते मुद्रास्फीति में और भी वृद्धि हुई है। मौद्रिक सहायता को क्रमिक रूप में वापस लिया जाना मुद्रास्फीति दबावों को सहन करने और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने में सहयोग दे रहा है जो ईंधन और खाद्य मूल्यों के चलते 2010-11 के बड़े हिस्से में उच्च स्तर पर बनी रही। नपा-तुला राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जो 2010-11 में पुनः आरंभ हुआ, मध्यावधि में भी जारी रहेगा तथा इस तरह से यह समग्र मांग पर से कुछ दबाव कम करेगा। संरचनात्मक रुकावटों को हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने और समावेशी वृद्धि की ओर पूर्व में की गई नीतिगत पहलों को मजबूती प्रदान करने को महत्त्व देने के साथ-साथ 2011-12 में की गई बजटीय पहलें इस दिशा में आगे बढ़ी हैं। तथापि, कच्चे तेल की उच्च कीमतों के चलते पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में संभावित वृद्धि व्यय पर दबाव बढ़ा सकती है। समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संभावित खतरों से बचाने के लिए पूंजी प्रवाहों का प्रबंधन एक अनवरत चुनौती है। मुद्रा बाजारों में कुछ सख्ती के बावजूद ऋण वृद्धि, इक्विटी बाजार की तेज गतिविधियों और एक स्थायी विदेशी मुद्रा बाजार में तेजी के साथ वित्तीय परिस्थितियां व्यवस्थित रहीं। मध्यावधि संभावनाएं सकारात्मक बनी रहीं। संभावित अधोमुखी जोखिम मुख्य रूप से ऊर्जा और पण्य मूल्यों के संबंध में जारी सतत अनिश्चितता से उत्पन्न होते हैं जो निवेश के वातावरण को नष्ट कर सकते हैं, परिणामस्वरूप वर्तमान में विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जोखिमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की गति बरकरार रखे हुए है।

श्रीलंका

17. तीन दशकों के गृह युद्ध और वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप आई गिरावट से उबरते हुए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता के माहौल में तेजी से बढ़ रही है। वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 2010 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसने शांतिपूर्ण देशी वातावरण, बढ़े हुए निवेशक विश्वास, मजबूत होते समष्टिआर्थिक आधारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्रमिक बहाली के चलते उच्च वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। मुद्रास्फीति में गिरावट और अनुकूल मुद्रास्फीति परिदृश्य ने समावेशी मौद्रिक नीति रख के जारी रहने में सहायता की है जिससे बाजार के सभी हिस्सों में ब्याज दर में कमी आई तथा आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्राप्त हुआ। हाल की बाढ़ ने कृषि उत्पादन को कुछ नुकसान पहुंचाया है जिसने पिछले

कुछ महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति को अपेक्षा से अधिक बढ़ाया है। तथापि, मूल-मुद्रास्फीति में गिरावट आई और वर्तमान में यह एक अंक के निम्न स्तर पर बनी हुई है। 2010 में समग्र राजकोषीय स्थिति में उत्साहवर्धक सुधार आया जिसमें आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, बार-बार होने वाले व्यय को रोकने, साथ ही साथ कर प्रणाली के कतिपय संरचनात्मक मुद्दों को हल करने संबंधी समर्थन के साथ सरकारी राजस्व की वसूली भी हुई। 2010 में बजटीय घाटा सकल देशी उत्पाद का 8.0 प्रतिशत रहा जो 2009 के 9.9 प्रतिशत से कम था और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति वचनबद्धता के फलस्वरूप 2011 में बजटीय घाटा और अधिक घटकर 6.8 प्रतिशत हो जाएगा और यह मध्यावधि में घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा। 2009 की दूसरी तिमाही से बाह्य क्षेत्र में अद्वितीय रूप से कायापलट हुई है और यह अभी भी विकास कर रहा है। आयात और निर्यात दोनों ही में सुधार हुआ जबकि पर्यटन उद्योग से बढ़ी हुई आय और उच्च आवक धनप्रेषणों के कारण बढ़ते हुए व्यापार घाटे की प्रतिपूर्ति हो गई जिससे बाह्य चालू खाते का घाटा सीमित हुआ। बढ़े हुए पूंजी और वित्तीय प्रवाहों के परिणामस्वरूप 2010 में भुगतान संतुलन में अतिरिक्त निधि दर्ज की गई, फलस्वरूप देश की बाह्य आरक्षित निधियां मजबूत हुईं। अनुकूल मौद्रिक वातावरण और मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे के कारण वित्तीय क्षेत्र ने प्रगति की और 2010 में प्रणालीगत स्थिरता मजबूत हुई जो कि विवेकपूर्ण संकेतकों में परिलक्षित है। बैंकों के ऋण प्रवाहों में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ, लाभप्रदता में सुधार हुआ, पूंजी पर्याप्तता प्रारंभिक सीमा से और अधिक बढ़ गई और अनर्जक परिसंपत्ति संबंधी ऋण के अनुपात में गिरावट आई, जबकि ऋण हानियों संबंधी प्रावधानों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, विश्व बाजार में उच्च खाद्य और ऊर्जा कीमतों के कारण बाह्य आघात, भुगतान संतुलन और मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए कुछ जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

18. ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय संकट की गर्त को हमने पीछे अवश्य छोड़ दिया है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सुधारों में मजबूती आई है, परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष पेश आ रही नई चुनौतियों के कारण यह अभी भी संवेदनशील है। हमें सुधार और पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न रहने के साथ ही नए पुराने खतरों से निपटने के लिए तैयार और सतर्क रहना होगा। आज हम जिन वैश्विक समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे जटिल हैं और उनका समाधान आसान नहीं है। उनमें से बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिए अक्सर राष्ट्रीय

स्तर पर कठिन सुधार करने पड़ते हैं और देशों में विभाजित दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कोई प्राकृतिक रूप से अनुकूल क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक सत्ता के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण कभी भी नहीं थी। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में देशों के ज्यादा से ज्यादा शामिल होने के कारण अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सभी के लिए बदतर परिणाम सामने आएंगे। हमें न केवल संकट से उबरने के लिए सहयोग

करना चाहिए अपितु यह सुनिश्चित कर लेने के लिए भी सहयोग करना चाहिए कि इस संकट से निपटते हुए कहीं हम अगले संकट के बीज न बो दें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का माहौल तैयार करने में सहयोग देना होगा। यह सभी के हित में होगा। हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस भूमिका के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है ताकि यह प्रासंगिक, तर्कसंगत और प्रभावी बना रहे।